

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
ब्रयोदश (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 17.07.2018 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०स०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री प्रदीप यादव स०वि०स०	<p>राज्य के प्रस्तीकृत (वित्त सहित) मदरसों एवं प्रस्तीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को 18 महीनों से बेतन नहीं मिला है। साथ ही सरकार ने संकल्प सं०-१६७४, दिनांक- 11.06.2018 द्वारा इन शिक्षकों के पेंशन आदि सुविधाओं पर रोक लगा दी है। सरकार का निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों में भेदभाव को प्रदर्शित करता है और इस निर्णय से मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में काफी रोष है। साथ ही कार्यरत कर्मियों को आर्थिक संकट से भी जुँड़ा पड़ रहा है।</p> <p>अतः सरकार इस पर पुनर्विचार करे इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।</p>	योजना सह-वित्त
02-	श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स०	झारखण्ड राज्य के निर्माण के बाद राज्य की राजधानी रौची की 18 वर्षों में तीव्रता के साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई है। रौची शहर की नगरीय सुविधा व व्यवस्था आज भी वही है, जो 18 वर्ष पूर्व वर्ष 2000 में थी। रौची शहर का मेन रोड, बरियातु, हरमु, कॉके, कचहरी, लालपुर, कोकर इत्यादि मुख्य	नगर विकास एवं आवास

कृ०पृ०३०

01.	02.	03.	04.
		<p>सङ्केती निवास कॉम्प्लेक्स, यीन एरिया एवं चौड़ी सड़को का आभाव है। वर्तमान राज्य सरकार, राँची शहर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है। आने वाले वर्षों में राँची शहर में बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव और अधिक बढ़ेगा।</p> <p>अतः आगामी 10 वर्षों को ध्यान में रखते हुए राँची शहर तथा आस-पास के क्षेत्रों में सड़कों का चौड़ीकरण, पार्किंग यीन एरिया, स्कूल, कॉलेज, यातायात सुविधा के लिए मोनो रेल तथा अन्य नगरीय सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।</p>	
03-	श्री अशोक कुमार एवं श्री अमित कुमार मण्डल स०वि०स०	<p>गोड्डा जिलान्तर्गत राजमहल कोयला खनन परियोजना द्वारा CBA Act के तहत अर्जित की गई भूमि पर परियोजना प्रभावित रैयतों का पुनर्वास व विस्थापन के कारण वैसे विस्थापित परिवारों को दिये गए भूखंड का आजतक मालिकाना हक नहीं मिला है। परियोजना द्वारा वर्ष- 1981 में कोयला उत्खनन कार्य हेतु CBA Act के तहत भूमि अधिग्रहण की गई थी, जिसके लिये रैयतों को 15 वर्ष की अवधि का छति-पूर्ति फसल मुआवजा दिया गया था एवं वैसे भूमि पर काफी वर्षों पूर्व उत्खनन का कार्य भी समाप्त हो चुका है एवं लीज की अवधि वर्ष 2003 में ही समाप्त हो चुकी है। CBA एकट के तहत अर्जित भूमि पर विस्थापन नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोयला खनन के पश्चात् जमीन का समतलीकरण कर भूमि को पूर्व की स्थिति में लाकर राज्य सरकार को वापस किया जाना है। खनन क्षेत्र के विस्थापितों का पुनर्वास हेतु LA Act के तहत परियोजना को भूमि का अधिग्रहण कर विस्थापित परिवारों को नियमानुसार भूमि आवंटित कर बसाने की प्रक्रिया किया जाना चाहिये। परन्तु राजमहल कोयला-</p>	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		<p>खनन परियोजना द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता है।</p> <p>अस्तु राज्य सरकार भू-विस्थापितों व भू-दाताओं को संरक्षण देते हुए CBA Act के तहत वर्ष- 1981 या उसके बाद अधिग्रहण की गई भूमि का पुनः मुल्यांकन करते हुए लीज की अवधि बढ़ाकर ऐयतों को मुआवजा दिलाने अथवा लीज समाप्ति के पश्चात नियमानुसार उनकी भूमि वापस कराने हेतु की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।</p>	
04-	श्रीमती शीमा देवी स०वि०स०,	<p>पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए NGT के आदेश के तहत नदियों से बालू खनन पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक रोक है। इस रोक के बावजूद राज्य के कई हिस्सों में माफिया एवं पदाधिकारियों/पुलिस की मिलीभगत से बालू का अवैध खनन होता है।</p> <p>अतः अवैध खनन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने एवं इसपर निगरानी हेतु विभाग के चेकनाका में CCTV कैमरा लगाने तथा बालू उठाव में प्रयोग आनेवाले वाहनों का खनन विभाग द्वारा विशेष परिमिट जारी करते हुए परमिटधारी वाहनों पर GPS सिस्टम अनिवार्य करने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहती है।</p>	उद्योग, खान, एवं भूतत्व
05-	श्रीमती विमला प्रधान, स०वि०स०	सिमडेगा जिला के सिमडेगा प्रखण्ड में कुल्लुकेरा पंचायत है, जिसमें 9 राजस्व ग्राम हैं। परन्तु पंचायत मुख्यालय कुल्लुकेरा में ही जन वितरण प्रणाली की राशन दुकाने हैं जबकि राजस्व ग्राम हाथाभाड़ी की दूरी 10 कि०मी० रावन खोल 8 कि०मी० चडरी ठोली 10.05 कि०मी०, बड़काडांड-8 कि०मी०, पटिया पाती-5 कि०मी० पाकेर कच्छर 5 कि०मी० झुण्डुपानी 9 कि०मी०, वनमारा 9 कि०मी० एवं चिरोबेडा 3 कि०मी० की दूरी पर है।	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

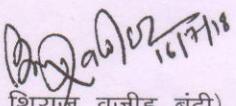
01.	02.	03.	04.
		<p>सिमडेगा जिला के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की समस्याएँ हैं। अतः सरकार की राशन वितरण योजना का लाभ कार्डधारियों को नहीं मिल पाता है, आगे-जाने की कठिनाई के कारण निर्धारित तिथि को लोग नहीं आ पाते हैं।</p> <p>अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हुए कहना है कि जिला के जंगली क्षेत्रों में जन सुविधा को देखते हुए जन वितरण प्रणाली की दुकान आवंटित की जाय जिससे कल्याणकारी योजना का लाभ आम लोगों को मिल सके।</p>	

राँची,
दिनांक- 17 जुलाई, 2018 ई०।

बिनय कुमार रिंग
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

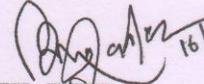
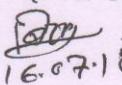
ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-४३/२०१८-.....3266.....वि० स०, राँची, दिनांक- 16/०७/१८

प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण, मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/योजना सह- वित्त विभाग/बगर विकास एवं आवास विभाग/राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(
(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-४३/२०१८-.....3266.....वि० स०, राँची, दिनांक- 16/०७/१८

प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

(
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

16/07/18

सुभाष/-